**एनकॉर कार्यक्रम: पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क**

**<u>कार्यकारी सारांश</u>**

### *1. परियोजना अवलोकन*

एनकॉर कार्यक्रम आठ साल के मल्टी फेज प्रोग्राममैटिक ऑपरेशन के रूप में प्रस्तावित किया गया है. एमपीए का चरण I; का लक्ष्य निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन को मजबूत करना है।
घटक 1. विकेन्द्रीकृत तटीय प्रबंधन के लिए बेहतर क्षमता
घटक 2. तटीय क्षेत्रों में बेहतर संरक्षण और प्रदूषण को कम करना
घटक 3. परियोजना प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन

प्रथम चरण के दौरान, तटीय भारत के आठ (08) राज्यों / और तीन (03) केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में परियोजना गतिविधियों को लागू किया जाएगा। इसमें तटीय प्रबंधन योजना तैयार करना और प्रदूषण उन्मूलन, तटीय संरक्षण और आजीविका से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक के निवेश परियोजना वित्तपोषण (IPF) उपकरण के तहत वित्त पोषित किया जाता है, और इसलिए इसकी सुरक्षा नीतियां इस पर लागू होती हैं।

### *2. पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे*

इस परियोजना से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें समुद्री और तटीय संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम, तटीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग और स्थायी तटीय आजीविका को बढ़ावा देना शामिल है। चूंकि इस परियोजना में पहले ही आईसीजेडएम योजना तैयार की जाएगी, सभी परियोजनाएं तटीय आवश्यकताओं पर आधारित होंगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना के कारण कोई बड़े पैमाने पर, महत्वपूर्ण या अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव नहीं हैं। हालांकि, छोटे निर्माण गतिविधियों के कारण निम्न से मध्यम नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

परियोजना के तहत निजी भूमि अधिग्रहण की परिकल्पना नहीं की गई है। मैंग्रोव वृक्षारोपण और छोटे बुनियादी ढांचे का निर्माण सार्वजनिक भूमि में किया जाएगा। श्रद्धापूर्वक प्लानिंग से परियोजना का गुण सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी हैं । परियोजना क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों की आमद भी नहीं है । परियोजना से समुदाय को सामान्य रूप से लाभ होगा

### *3. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचा*

भारत सरकार के पर्यावरण और सामाजिक नियमों और विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों का अनुपालन करने के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचे को सोसाइटी ऑफ़ कोस्टल मैनेजमेंट रेखांकित किया। यह फील्ड टूर, हितधारक परामर्श, और उपलब्ध माध्यमिक डेटा की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया था।
यह भारत सरकार के पर्यावरण नियमों और विश्व बैंक की पर्यावरण नियमों के साथ सभी परियोजना गतिविधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है।

ईएसएमएफ परियोजना राज्यों की पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, और (i) सबप्रोजेक्ट्स के लिए स्क्रीनिंग चेकलिस्ट, [ii] संभाव्य प्रभावों के लिए शमन उपायों, [iii] यदि आवश्यक हो तो परियोजना विशिष्ट उपकरणों को विकसित करने की प्रक्रियाएं, [ iv] कार्यान्वयन तंत्र, और [v] निगरानी प्रक्रियाओं प्रस्तुत करता है ।

### *4. पर्यावरण और सामाजिक नियामक ढांचा*

राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पर्यावरणीय कानून और विश्व बैंक की परिचालन नीतियां नीरंचल वित्त पोषित उपप्रोजेक्ट पर लागू होंगी। भारत सरकार के तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019, पर्यावरण [संरक्षण] अधिनियम, 1986, जल [प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण] अधिनियम 1974, वन [संरक्षण] अधिनियम 1980, वायु [रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण] अधिनियम 1981, इत्यादि अनेक नियम लागू होगा. विश्व बैंक के ओपी / बीपी 4.01, 4.04, 4.09, 4.36 और 4.11, पर्यावरण इत्यादि सम्बंधित नियम भी लागू होगा.

प्रासंगिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सामाजिक कानून हैं: आरटीएफसीटीएलएआरआर 2013; भूमि अधिग्रहण पर राज्य स्तरीय कार्य / नीति / विनियमन; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी [वन अधिकारों की पहचान] अधिनियम 2006; सूचना का अधिकार अधिनियम 2005; और विश्व बैंक परिचालन नीतियां ओपी 4.12 अनौपचारिक पुनर्वास पर, 4.10 स्वदेशी पीपुल्स और सूचना और प्रकटीकरण तक पहुंच पर नीति।

विश्व बैंक के OP4.01 के अनुसार एनकॉर परियोजना से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होने की उम्मीद है और इसलिए प्रोजेक्ट 'ए' श्रेणी में आता है ।

### *5. पर्यावरण स्क्रीनिंग और सबप्रोजेक्ट्स का वर्गीकरण*

परियोजनाओं के स्थान और परियोजना गतिविधियों के आधार पर, ग्रामीण और पेरी-शहरी पर्यावरण पर अलग-अलग प्रभाव हो सकते हैं। प्रभावों की गंभीरता के आधार पर सबप्रोजेक्ट्स को ई ए, ई बी और ई सी वर्गीकृत किया जा सकता है । ई ए परियोजनाओं से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होने की उम्मीद है और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पर्यावरणीय आकलन की तैयारी की आवश्यकता होगी। डीपीआर के हिस्से के रूप में पर्यावरणीय मूल्यांकन की तैयारी होगी तो एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसका समीक्षा होना जरूरी हैं.

ई बी परियोजनाओं से मध्यम प्रभाव होने की उम्मीद है और डीपीआर के हिस्से के रूप में पर्यावरणीय मूल्यांकन की तैयारी की आवश्यकता होगी; और ईसी परियोजनाओं से कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव होने की उम्मीद है और केवल जेनेरिक ईएमपी की तैयारी की आवश्यकता होगी। सामान्य ईएमपी ईएसएमएफ में प्रस्तुत किया गया है।

जबकि सूचीबद्ध पुरातात्विक स्थलों या महत्वपूर्ण स्मारकों के निकटता [300 मीटर त्रिज्या] में परियोजना गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्य प्रमुख लेकिन असूचीबद्ध संपत्तियों के लिए, शारीरिक भौतिक सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (पीसीआरएमपी) विकसित करने का प्रस्ताव ईएसएम्ऍफ़ में है । पीसीआरएमएफ के संभावना खोज प्रक्रिया भी ईएसएम्ऍफ़ शामिल है। पर्यावरणीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों, और जंगलों में परियोजनाओं का प्रबंधन करने के तरीके, ईएसएम्ऍफ़ में शामिल हैं। कृषि परियोजनाओं में कीटों और पोषक तत्वों का प्रबंधन करने की योजना ईएसएम्ऍफ़ में मौजूद है। समुदाय और श्रम स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रभावों के लिए शमन उपायों को भी ईएसएमएफ में शामिल किया गया है।

### *6. सबप्रोजेक्ट्स का सामाजिक वर्गीकरण*

प्रभावों की गंभीरता के आधार पर, ईएसएमएफ ने सबप्रोजेक्ट को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जैसे कि एसए, एसबी और एससी। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स विभिन्न प्रभाव श्रेणियों के लिए शमन उपायों प्रदान करता है जैसे कि भूमि, आवासीय संरचनाओं, वाणिज्यिक संरचनाओं, सामुदायिक संपत्तियों, शीर्षक धारकों पर प्रभाव, किरायेदारों और पट्टेदारों, गैर-शीर्षक धारकों, आजीविका का नुकसान, कमजोर परिवारों पर असर, और अज्ञात प्रभाव और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 और ओपी 4.12 के अनुसार है। विश्व बैंक के 12, और पुनर्वास कार्रवाई योजना [आरएपी] की तैयारी की आवश्यकता है।

### *7. पुनर्स्थापन नीति ढांचा*

पुनर्वास नीति ढांचे के प्रमुख सिद्धांत सामाजिक प्रबंधन ढांचे का मूल उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन से प्रभावित आबादी को सामाजिक प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। ढांचा यह भी जोर देता है कि जहां भी संभव हो, अलग-अलग विकल्पों की खोज करके अनैच्छिक पुनर्वास से बचा जाएगा और कम किया जाएगा। ईएसएमएफ भारत सरकार के भू-अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास [आरटीएफसीटीएलएआरआर] अधिनियम 2013 में भूमि अधिग्रहण और पारदर्शिता पर निष्पक्ष क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता पर विश्व बैंक की नीति के बीच का अंतर पुल करता है। आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की व्यापक श्रेणियां कम हो जाएंगी: • भूमि और परिसंपत्तियों का नुकसान; • आश्रय या घर की भूमि का नुकसान; • आजीविका के आय या साधनों का नुकसान; • उत्पादक संसाधनों, आश्रय / निवासों तक पहुंच का नुकसान; और • समुदाय संपत्तियों, आम संपत्ति संसाधनों और अन्य लोगों के नुकसान जैसे समूहों पर सामूहिक प्रभावों का नुकसान।

### *8. संस्थागत ढांचा*

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तटीय प्रबंधन की एजेंसी है सोसाइटी ऑफ़ कोस्टल मैनेजमेंट जो एनकॉर के राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधक (एन पी एम यू) है। प्रत्येक राज्य में राज्य परियोजना प्रबंधक होगा, जो ज्यादातर पर्यावरण विभाग होगा । विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी। वे सरकारी विभाग, निजी या स्वैच्छिक संगठन या सामुदायिक संगठन हो सकते हैं। ईएसएमएफ के कार्यान्वयन को समन्वय और निगरानी करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव के साथ समर्पित पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञ और लिंग विशेषज्ञ होना चाहिए। ईएसएमएफ इसके संस्थागत तंत्र भी प्रस्तुत करता है।

### *9. सबप्रोजेक्ट तैयारी*

ईएसए और ईएमपी और आरएपी का गैर-तकनीकी सारांश (अंग्रेजी / हिंदी दोनों में) के साथ अंतिम संस्करण संबंधित विभागों / मंत्रालयों की वेबसाइटों पर खुलासा किया जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए सुलभ स्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा के लिए सबप्रोजेक्ट स्वीकृति निम्नलिखित उपप्रोजेक्ट अनुमोदन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

i) उपरोक्त परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के लिए ईएसएमएफ की सहमत नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य स्तर एजेंसियों (एस पी एम यू) और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीईए) द्वारा जांच की जाएगी और तदनुसार परियोजना के पर्यावरण और सामाजिक वर्ग को निर्धारित एस पी एम यू से किया जाएगा (ईएसएमएफ में स्थापित मानदंड के अनुसार)।

ii) इसके बाद प्रत्येक उपप्रोजेक्ट, ईएमपी और आरएपी तैयार किया जाएगा। समीक्षा के बाद सबप्रोजेक्ट्स की ड्राफ्ट रिपोर्ट और ई ए श्रेणी की पर्यावरणीय प्रभाव आश्वासन रिपोर्ट एस पी एम यू विश्व बैंक को समीक्षा और मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. इसका उपयोग राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर निकासी के लिए भी किया जाएगा ।

iii) प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर एजेंसियों (एस पी एम यू) और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीईए) द्वारा सबप्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। पीईए के माध्यम से ईएसएमएफ के अनुसार सभी उपप्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। एस पी एम यू मासिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीईए और अन्य संस्थानों के साथ समन्वय करेंगे।

iv) उप-प्रोजेक्ट स्थानों के क्षेत्रीय दौरे के आधार पर संबंधित एस पी एम यू और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की पर्यावरणीय और सामाजिक अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से एन पी एम यू द्वारा पर्यावरण और सामाजिक घटकों की निगरानी की जाएगी।

v) ईएमपी, आरएपी / एआरएपी का वार्षिक सुरक्षा लेखा परीक्षा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाएगी और लेखा परीक्षा की सिफारिश संबंधित उपप्रोजेक्ट्स और परियोजना में लागू की जाएगी।

### *10. शिक्षण और क्षमता निर्माण*

एनकॉर परियोजना में पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों और उपप्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी पहलुओं पर हितधारकों (एन पी एम यू, रेखा विभाग, समुदायों, ठेकेदारों, मजदूरों सहित) की क्षमता बनाने की योजना है। एक्सपोजर विज़िट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में भागीदारी के माध्यम से कर्मचारियों और पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। स्टेकहोल्डर परामर्श और प्रकटीकरण ईएसएमएफ की तैयारी के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्तर पर विभिन्न परामर्श आयोजित किए गए। परियोजना के विभिन्न चरणों में परामर्श और शामिल शेयरधारकों का विवरण ईएसएमएफ में प्रस्तुत किया गया है। उप परियोजना ईआईए के लिए सुझाए गए परामर्श में फील्ड सर्वेक्षण, फोकस समूह चर्चा और हितधारक मीटिंग शामिल हैं। राष्ट्रीय और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परामर्श और प्रकटीकरण प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

### *11. ईएसएमएफ का खुलासा*

एन पी एम यू ने अपने वेबसाइट पर ईएसएमएफ का खुलासा 7 जून 2019 को किया था [हिंदी अनुवाद के साथ] और आम जनता को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इसका अधिसूचित किया गया था। वर्ल्ड बैंक इंफॉशॉप में ड्राफ्ट ईएसएमएफ का भी खुलासा 1 अगस्त 2019 को किया गया था। हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को शामिल करने के बाद अंतिम रिपोर्ट, एन पी एम यू, एस पी एम यू और विश्व बैंक द्वारा फिर से खुलासा किया जाएगा।